[Secretary]

(2) The Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1972.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

SEVENTH REPORT

SHRI S. C. SAMANTA (TAMLUK) : I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

---

13 hrs.

ANTIQUITIES AND ART TREASURES BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will take up further consideration of the following motion moved by Prof. S. Nurul Hasan on the 23rd August, 1972, namely :—

> "That the Bill to regulate the export trade in antiquities and art treasures, to provide for the prevention of smuggling of, and fraudulent dealings in, antiquities, to provide for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures for preservation in public places and to provide for certain other matters connected therewith or incidental or ancillary thereto, be taken into consideration".

Shri Rudra Pratap Singh may now continue his speech.

श्री रुद्र प्रताप सिंह (बाराबंकी) : मान्यवर, मैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक, 1972 पर अपने विचार प्रकट कर रहा था।

श्रीमन्,

समय की शिला पर मधुर चित्र कितने,
किसी ने बनाये, किसी ने मिटाये।

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत पर कुछ आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारे पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति के रूप में थे, उन्हें नष्ट किया है तथा उन्हें लूटा है। साथ ही साथ श्रीमन्, माननीय सदन इस बात से भी सहमत है कि कुछ विदेशी शासकों ने भी देश की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको लूटा है और उनकी चोरी की है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी देश में कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो आज भी उसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। वे अब भी या तो सार्वजनिक स्थानों से हमारी बहुमूल्य वस्तुओं और कलाकृतियों की चोरी कर लेते हैं अथवा उनको सस्ते मूल्यों पर खरीदते हैं और उसके पश्चात् वे विदेशियों के हाथ में उनकी बिक्री करते है या उन्हें उपहार के रूप में देते हैं। यह स्थिति बहुत गम्भीर है। इसके साथ-साथ कभी-कभी देश के बड़े पूजीपति उन तमाम बहुमूल्य कलाकृतियों को, पुरावशेषों को अपने प्रासादों में अपनी अट्टालिकाओं मे अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग करते है और उसके द्वारा अपनी वासना की तृप्ति और पिपासा की पूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि देश के पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियां जो निजी क्षेत्र में है उनको सरकारी क्षेत्र में ले आया जाये। कला देवी का मन्दिर सभी के लिए खुला होना चाहिए केवल पूंजीपतियों के लिए ही नहीं। कला बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होनी चाहिए, स्वान्तःसुखाय नहीं होनी चाहिए। देश के पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियां हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, वे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं रह सकती हैं। मैं अपने दल की नेता, राष्ट्र की प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को और अपने शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति की धरोहर है उनकी किस प्रकार से रक्षा की जाये, किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति का गौरव और गरिमा स्थापित रह सके इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक बहुत ही गम्भीरतापूर्वक चिन्तन, मनन और अध्ययन करने के पश्चात् इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं कि इस देश की संस्कृति की रक्षा हो। इस माननीय सदन के माननीय सदस्य, चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों अथवा उस पक्ष में बैठने

वाले हों, सभी को देश की संस्कृति से लगाव है, सभी को देश की संस्कृति से प्यार है, सभी इस बात से सहमत होंगे।

अन्त में मैं माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक देश के पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृतियों का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें हर सम्भव प्रयास करने होंगे और यह प्रयास केवल इस दृष्टि से नहीं कि हमें कला के प्रति अनुराग है, कला के प्रति राग है बल्कि इसलिए और इस दृष्टि से हमें कार्य करना होगा कि हमें देश की संस्कृति के प्रति स्नेह है, देश की संस्कृति के प्रति आदर है और देश की संस्कृति हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इस प्रश्न को हम राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में विचार करेंगे। इस विधेयक के द्वारा जो व्यवस्था की गई है कि जो अभी देश में जिस तरह से कलाकृतियों की चोरियां हो रही हैं, जिस प्रकार से देश में अब भी तस्करी का व्यापार कलाकृतियों का हो रहा है और साथ ही साथ अब भी पूंजीपतियों के पास जो कलाकृतियां जाकर देशद्रोहियों के द्वारा देश के बाहर भेजी जाती हैं उन पर किस तरह से नियन्त्रण किया जाये, किस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर, जो कलाकृतियां अभी निजी क्षेत्रों में पड़ी हुई हैं उनको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सरकार अधिग्रहण करे और साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि यदि वे विधेयकों के अनुरूप कार्य और आचरण न करें तो उन्हें किस प्रकार से दण्डित किया जाए—मैं समझता हूं यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का हित निहित है। मैं समझता हूं इस विधेयक पर हमारे किसी भी माननीय सदस्य को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

अन्त में मैं माननीय सदन का बहुत समय न लेकर केवल यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं :

क्या खबर है कोशिशे नाकाम ही काम आ जाये।
मेरे आगाज़ पे हंगामा मगर अंजाम के बाद।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : मान्यवर, संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारत की संस्कृति भी एक है। भारत पुरातनतम देशों में एक है। भारतीय, चीनी, मिस्री, सेमेटिक सभ्यतायें संसार की सबसे पुरानी सभ्यतायें रही हैं। हमारे देश में इसी कारण प्राचीन काल, मध्य युगीन और अर्वाचीन—तीनों काल की कलाकृतियां और पुरावशेष पूरे देश में बिखरे पड़े हुए हैं। चूंकि लिखी हुई प्राचीन चीजें हमारे पास बहुत कम हैं इसलिए इन्हीं कलाकृतियों, इन्हीं पुरावशेषों के बल से हम अपने इतिहास के बहुत से पुराने पन्नों को खोज पा रहे हैं। चूंकि समय कम है इसलिए सुझावों से ही मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

जहां तक मुझे याद है हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रथम डायरेक्टर, निदेशक डा० ग्रेस मार्लें नियुक्त की गई थीं। वे इस विषय की अमरीकी विशेषज्ञ थीं। जहां तक मेरी सूचना है हमारे देश की कलाकृतियों और पुरावशेषों के बाहर और विशेषकर अमरीका जाने का जो कुत्सित व्यापार शुरू हुआ यह उन्हीं के जघन्य कृत्य का फल रहा है। इस कार्य में उनको सहायता बहुत से आर्कियालोजिकल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से मिली, बहुत से राजा महाराजाओं और दूसरे जो संग्रहालय हैं उनके डायरेक्टरों से मिली। साथ ही साथ सरकार के अनेक विभागों के उच्च-पदाधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में उनको सहायता मिलती रही है। आज जहां तक मुझे पता है वे इसी देश में कहीं पर बसी हुई हैं। मेरा आग्रह है सरकार से कि उन पर पूरी निगाह रखी जाए। अब भी वे लुके-छिपे इस व्यापार में लगी हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। इस विधेयक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारी कलाकृतियां, हमारे पुरावशेष बाहर न जायें। जयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम से बहुत सी चीजें हमारे देश से बाहर जा चुकी हैं।

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR (Jaipur) : I object to that. That is a personal allegation against Jaipur City Palace Museum. Not one thing has gone out of the palace for sale, except for five carpets

[Shrimati Gyatri Devi]

which we offered first to the National Museum and then they were sent and sold abroad. There has been a theft in the City Palace Museum about the same time as there was one in the National Museum, and the CBI is investigating it. Not one thing has gone out of the City Palace collection. We are trying to acquire ; not sell. It is a museum ; not a private collection. It is a trust formed in 1958.

श्री झारखण्डे राय : माननीया सदस्या का कथन सरकार को नोट करना चाहिए और जो मेरा सन्देह है उसको भी नोट करना चाहिए और पूरी जांच करनी चाहिए कि सत्य और तथ्य कहां पर हैं। आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल भी एक संग्रहालय के जो निदेशक थे उनके साथ षड्यन्त्र में शामिल थे। मेरा कहना है कि इस पूरे कुत्सित व्यापार में ऊँचे-ऊँचे आदमी शामिल रहे हैं। इसलिए उन पर कड़े कदम उठाये जाने चाहिएं। मुर्शीदाबाद का महल जिसे वहां की भाषा में दरबार हजारी कहते हैं, वहां से अनगिनत कलाकृतियां और पुरावशेष हमारे देश के बाहर जा चुके हैं। इसकी पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि सरकार को इस बात का पता तब लगा जब करीब-करीब देश के सभी अखबारों में इसके समाचार छापे जा चुके थे। सरकार की कितनी विजिलेन्स है यह इस बात का प्रमाण है। इस लिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि कम से कम दो साल के लिए पूरी एक्सपोर्ट ट्रेड को बन्द कर दिया जाये। अगर पूरी दुनिया से नहीं बन्द किया जा सके तो कम से कम अमरीका से तो हर हालत में बन्द होना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में अमरीका को जितना सामान हमारे यहां से गया है उतना शायद पूरी दुनिया को नहीं गया है। अमरीका ने जितना कुत्सित व्यापार हमारे यहां प्रोत्साहित किया है उतना किसी ने नहीं किया। हां, यह बात है कि जिन देशों से हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिलती-जुलती हो, जिनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मिलती-जुलती हो उनके साथ इस तरह के व्यापार की आज्ञा दी जा सकती है, जैसे सोवियत यूनियन, अमरीका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और मैक्सिको है। लेकिन किसी भी हालत में ब्रिटेन से, यूरोप के दूसरे देशों से और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह काम अब एक नियमित व्यापार और व्यवसाय हो गया है।

इस विधेयक में गांवों की चर्चा है कि जो लाइसेंस लेना चाहें वह किस गांव से इस का व्यापार करेंगे उसकी भी चर्चा हो। मैं सोचता हूँ कि गांवों में इस व्यापार और व्यवसाय के केन्द्र हरगिज नहीं खोले जाने चाहिएँ, और न ही इस की आज्ञा देनी चाहिए। क्योंकि इन पिछले दिनों में गांवों के बहुत से लोगों ने हिन्दुस्तान के बिखरे हुए मन्दिरों से मूर्तियों की चोरियां कीं। दूर-दूर पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थान हैं वहां मन्दिरों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अनेक देव स्थानों में पुजारी भी नहीं होता, वहां से मूर्तियो की चोरियां बड़ी आसानी से होती हैं। ऐसी स्थिति मे गांवों में इस तरह के व्यवसाय की आज्ञा किसी प्रकार के लाइसेंसी को नहीं देनी चाहिए। भारतवर्ष में ऐसी एजेन्सीज हैं जिनका यह रेगुलर ट्रेड हो चुका है। मेरा सुझाव है कि जो लोग इस तरह का काम करते हुए एक बार पकड़े जायें उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए; उन्हें कभी भी किसी प्रकार से ऐसे व्यवसाय की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। एक नई धारणा की इस विषय में हमको जरूरत है।

भूतपूर्व नरेशों के जो संग्रहालय हैं, मेरा आग्रह है कि सरकार को उन्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जब तक उनकी रियासतें थीं, उन का रख-रखाव कुछ सम्भव था। लेकिन अब उनके लिए व्यावहारिक और सम्भव भी नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनमें से चोरियां आसानी से की जा रही हैं और यह भी सम्भव है, सही है, कि बहुत से भूतपूर्व नरेशों ने अपना खर्च चलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया है और बड़ी अच्छी रकमें लेकर उन्हें बाहर बेच रहे हैं और भेज रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार को अब इन तमाम संग्रहालयों को अपने हाथ में लेना चाहिए।

मान्यवर, दिल्ली में कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो इसके लिए कुख्यात हैं, जैसे नारंग फर्म है, निरूलास है और दूसरी साउथ ऐक्सटेंशन मे ऐसी फर्म्स हैं जिनका नियमित व्यापार हो गया है मूर्तियों को, तस्वीरों को, कलाकृतियों को, पुरावशेषों को देश के कोने-कोने से चुरवा कर मंगवाना और उनकी अच्छी कीमत लेकर बाहर बेच देना इसमे उन्हें पुलिस से भी सहायता मिलती है। आश्चर्य यह है कि भगवान के मन्दिरो से मूर्तियां चोरी जाती हैं लेकिन भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, तो हम इन्सानों को उन की रक्षा के लिए आगे आना पडेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी फ़र्म्स जो इस तरह के काम मे लगी हुई है उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, इनका स्टाक जब्त करना चाहिए और कम से कम 10 साल के लिए उन्हे इस व्यवसाय की आज्ञा नही देनी चाहिए।

इनमे लाइसेस फीस की भी बात है। उसमें विशेषता है। कही कम और कही ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि यह धारा करप्शन को बढ़ायेगी। इसलिए लाइसेंस फ़ी एक प्रकार की होनी चाहिए। वरना, जो अधिक लाइसेंस फी देने वाले है वे आसानी से ले लेंगे और जो कम लाइसेंस फी देंगे वह लाइसेंस नही पा सकेंगे। इस तरह की विषमता का भाव इसमे नही रखना चाहिए।

इस विधेयक मे आर्बिट्रेशन की भी चर्चा है। इसके बारे मे मेरा सुझाव है कि एक फिक्सड पैनल होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर इस काम को नही छोडना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उस पैनल में इस सदन का एक माननीय सदस्य हो, एक पुलिस अधिकारी रहे और तीसरा जो विषय का जानकार हो उसे रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक में रजिस्टरों की चर्चा है। मेरा निवेदन है कि केवल रजिस्टरों से काम नहीं चलेगा क्योंकि श्रीमन्, आप जानते हैं कि रजिस्टर दो तरह के होते हैं—एक असली और एक नकली। नकली पुलिस के लिए है और असली कुछ लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो व्यापार करते हैं। इसलिए केवल रजिस्टरों से काम नही चलेगा। जिनको लाइसेंस दिया जाए उनके लिए भी कुछ नियम बनने चाहिएं। नियम इस तरह के हों कि कौन सा व्यापारी किस युग की कलाकृतियों और पुरावशेषों मे व्यापार करना चाहता है, वह उसी युग की चीजों का संग्रह करें, उन्हीं को बेचे, उन्हीं को खरीदें। यह नहीं होना चाहिए कि वह अर्वाचीन युग की वस्तुओं का व्यापार करता है, तो वह मध्ययुगीन और प्राचीन, सभी मे व्यापार कर सकें, जहां भी जैसे चाहे सब पर हाथ मारे, यह स्थिति ठीक नही है। कौन फर्म किस देश से व्यापार करे यह भी निश्चित हो जाना चाहिए।

सजायें सख्त होनी चाहियें। जो सजायें रखी गई है वह कम हैं। जो भगवान की चोरी करने से बाज नही आते है, जो परलोक से नहीं डरते है, कहते हैं कि खुदा कहर करता है, ऐसे लोगों पर खुदा भी कहर नही करता, तो ऐसे लोगों के लिए दो महीने, तीन महीने और 6 महीने की कुछ सजायें नही हैं उनको कडी से कड़ी सजायें होनी चाहिए। इनकी सजा कम से कम पांच साल की होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

इस विधेयक मे नक्कालबाजों से भी बचने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग नकली वस्तुएँ बना कर न बेच सकें। नकली बनाकर असली के रूप में बेचते हैं, या व्यापार करते हैं, इसकी पूरी छानबीन और पूरी रक्षा इस विधेयक के द्वारा होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट लोगों के संग्रहालय है, या भूतपूर्व नरेशों के है, या बड़े-बड़े व्यापारियों के हैं, जैसे मोदी, सिंहानिया, भरत राम आदि के जो संग्रहालय हैं इन सब को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और जो सरकार नही लेना चाहती, उनमें क्या चीजें हैं, कब की हैं, कितनी है, इन सबका रेकार्ड सरकार के पास होना चाहिए।

सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सारे कुत्सित व्यापार का मुख्य केन्द्र दिल्ली है। जहां दिल्ली बहुत से अच्छे कामों का केन्द्र है, उसी तरह से इस कुत्सित व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र दिल्ली हो गया है। इसलिए दिल्ली के ऊपर सरकार की और इंटेलीजेंस विभाग की कड़ी निगाह होनी चाहिए। एक

[श्री झारखण्डे राय]

व्यापारी अपने स्वामित्व का परिवर्तन करना चाहता है तो इस पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए कि वह स्वामित्व जिस पीरियड का करता हो, वह ट्रांसफर करे, बेचे तो उसी पीरियड वाले व्यापारी को अपनी चीज बे। यह नहीं कि अर्वाचीन काल में व्यवसाय करते हैं तो प्राचीन काल वाले को बेच दे।

इस विधेयक में धार्मिक स्थान की भी चर्चा है। धार्मिक स्थान की पवित्रता की हमेशा चर्चा होती रही है, और इसके पीछे बहुत से व्यापार और व्यवसाय छिपाये जाते रहे हैं। यह सर्वविदित है कि धार्मिक स्थान, हर तरह के धार्मिक स्थान राजनीति के केन्द्र बन रहे हैं, और आज भी एक विशेष उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाते है। यही नहीं इन स्थानों का इस्तेमाल इस प्रकार के कुत्सित व्यापार, चोरी का माल छिपाने आदि के लिए भी किया जाता है, और पवित्रता के नाम पर संदेह होने पर भी उन की तलाशी न हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर संदेह होता है कि फलां धार्मिक स्थान ऐसा केन्द्र बन चुका है तो उसकी तलाशी लेने में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से मन्दिरों के पुजारी, मस्जिदों के मुल्ला, ऐसे धार्मिक स्थानों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वे ऐसे कामों को कराते हैं और माल छिपाते हैं। इसलिए उनकी अखंड पवित्रता के नाम पर इन जगहों की शक होने पर तलाशी लेने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। या जो शैक्षणिक संस्थायें हैं उनके बारे में भी मुझे यही कहना है कि शक होने पर तलाशी लेने में कोई कोताही नही होनी चाहिए। इसमें मुआवजे की बात कही गई हैं। इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि मार्केट वैल्यू एक बहुत गोलमोल शब्द है। इसका पता लगाना मुश्किल है। कोई आदमी 500 या 600 रुपये का सामान खरीदता है लेकिन उसको वह एक रुपये में बेच सकता है। इसलिए मार्केट वैल्यू का पता लगाना मुश्किल काम है। जो आदमी कोई कलाकृति की चोरी कर के लाता है उसके निकट उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो भी चोरी का माल खरीदता है वह बहुत कम पैसों में लेता है लेकिन एक लाख रुपये में बेच सकता है। इसलिए मुआवजे की रकम सोच समझकर रखी जानी चाहिये ताकि इस तरह के व्यापारियों को इसके लिए प्रोत्साहन न मिले।

मैं आप को एक सुझाव देना चाहता हूँ। केन्द्र में इस विषय पर एक स्थायी समिति, स्टेन्डिंग कमेटी, होनी चाहिये जिसमें एक विधायक हो, एक विशेषज्ञ भी हो और एक पुलिस अधिकारी भी हो और उनकी देखरेख में पूरे देश की कलाकृतियों की देख-भाल की व्यवस्था सम्पन्न होनी चाहिये।

इस विधेयक की मंशा बहुत ही उत्तम है। इसमें कुछ कमियां जरूर हैं लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। मगर यह चाहता हूं कि अगर हो सके तो इससे भी अधिक विस्तृत विधेयक के लिये तैयार किया जाय। अब तक के अनुभव के आधार पर और इस विधेयक के लागू होने के बाद उससे प्राप्त अनुभव के बाद विधेयक लाया जाय ताकि देश की जो पुरातन कलाकृतियां हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जा सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐन्टिक्विटीज एक्स्पोर्ट कंट्रोल ऐक्ट 1947 मे बना था। 1947 के बाद आज इतने साल हो गये हैं, इस सारे समय में कितनी इस तरह की चीजें एक्स्पोर्ट हुई, मेरे ख्याल से माननीय मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। सवाल यह किया गया था कि देश के अन्दर आज तक के दस वर्षों में कितना माल चोरी गया है। आप का उत्तर था कि 100 करोड़ रुपये का माल ऐन्टिक्विटीज और आर्ट्स आब्जेक्ट्स चोरी गये हैं। उन्होंने राज्य सभा में इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा था कि पिछले तीन वर्षों में कुल मिला कर 2182 आर्ट्स आब्जेक्ट्स चोरी गये हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि मुख्यतः इन चीजों के चोरी जाने के कारण यह विधेयक लाया गया है। अब तक जितने एजुकेशन मिनिस्टर हुए सभी ने यह कहा। डा० राव ने कहा, श्री नुरुलहसन ने कहा और आप ने भी कहा इस बात को। हमारे मंत्री

महोदय कला के बड़े प्रेमी हैं, शिक्षाशास्त्री भी है और सारी बात को समझते होंगे। वह कलाकार भी हैं।

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : I plead not guilty.

श्री मूलचन्द डागा आप कलाप्रेमी हैं। यह बडा अच्छा गुण है। लेकिन मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं। विज्ञान ने दुनिया को छोटा बनाया और कला ने दुनिया को सुन्दर बनाया। मान लीजिये हमारे शिक्षा मंत्री कोई ऐन्टिक्विटी की चीज हिन्दुस्तान से ले जाकर अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर को भेंट करना चाहे या किसी वी आई पी को देना चाहे तो वह इस चीज को ले जा सकते हैं या नही ? अगर इस देश का कोई बहुत बडा आदमी, जैसे अध्यक्ष महोदय, आप हैं, किसी दूसरे देश मे जाकर वहा के किसी बड़े आदमी को कोई इस तरह की चीज भेंट करना चाहें तो कह दिया जायेगा यहां पर इस पर बैन है। आप शायद यह कहेंगे कि संस्कृति का यह मतलब नही था। आप ने जिस चीज को इस ऐक्ट मे डाला है उसका यह मंशा नही था।

सवाल यह था कि हमारी सस्कृति की जो वस्तुयें हैं, ललितकला की जो वस्तुये है वह यहां से एक्स्पोर्ट न हो जाये, हमारी सस्कृति की रक्षा करने के लिये आप इस तरह की चीजो को रोकना चाहते हैं। लेकिन आप ने कह दिया— पहले भी जो आप का ऐक्ट था उस में यह बात थी और 1947 का जो ऐक्ट था उसमें भी यह था कि :

"Antiquities Export Control Act. 1947.

"No person shall export any antiquity except under the authority of a licence granted by the Central Government."

मैंने एक प्रश्न मंत्री महोदय से किया था। मान लीजिये कि 1947 के बाद हमारे यहां कोई आदमी अन्तर्जातीय विवाह करता है और वह अपनी पत्नी को बाहर जाकर कोई आर्ट की चीज भेंट करना चाहता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है। आप कहेंगे कि यू आर डिबार्ड। आप का जो सेक्शन 3 था उसमें यह था कि अगर कोई हिन्दुस्तान की किसी कला-कृति को बाहर ले जाना चाहता है तो वह उसके लिये परमिशन ले सकता है अब आप ने जो कानून बनाया है उसमें यह बिल्कुल मना है। इससे हिन्दुस्तान के कलाकारों और कलाप्रेमियो को तक्लीफ हो जायेगी। अगर किसी के पास कोई बड़ा अच्छा ड्राइंग रूम है और वह कला का प्रेमी है, कला की रक्षा करने वाला है, कोई बड़ा कवि है, शायर है, वह अपने घर मे कोई आर्ट की चीज रखना चाहता है चाहे वह कितनी ही कीमत का हो, तो जैसा एजुकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं, उसको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। वह कहता है कि नही, मैंने तो यह दरवाजा देखा ही नही। फिर आप कहते हैं कि उसे लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी चीज को बेचना होगा तो आप कहते है कि **विदइन दि प्रेस्काइब्ड टाइम** बेचना होगा।

मैंने ऐसा बिल कभी नहीं देखा जिसमें सारी चीजो के लिये लिख दिया जाय ऐज प्रेस्काइब्ड। मैंने इस बिल के सारे क्लाजेज देखे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है यह देखकर कि हम बहुत जल्दी में लेजिस्लेशन लाया करते हैं। आपने कहा कि हम गलतियां करते हैं। लेकिन आप ने इसमे अन्दर कोई प्रेस्काइब्ड की डेफिनिशन नही दी।

आप कृपा करके सेक्शन 8 लीजिये। उसमें लिखा हुआ है :

Every licence granted under this section shall be on payment of such fees as may be prescribed.

Every licence granted under this section shall for such period, subject to such conditions and in such form and shall contain such particulars, as may be prescribed.

Cl. 9 ; (1) A licence granted under Section 8 may, on an application made by the licencee, be renewed by the licensing officer for such

[श्री सूरजचन्द डागा]

period and on payment of such fees as may be prescribed.

Cl. 10 (1) Every holder of a licence granted under section 8.. shall maintain such records, photographs.. such particulars, as may be prescribed."

13·28 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप को पावर्स डेलिगेट ही करना है तो फिर आप बिल रखते ही क्यों हैं ? फीज डेलिगेटेड, टैक्स डेलिगेटेड, सब कुछ डेलिगेटेड है । मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जितने भी सेक्शन हैं उनमें आप क्यों डेलिगेटेड पावर्स देना चाहते हैं । आखिर डेलिगेटेड पावर्स देने से क्या होता है कि एग्जिक्यूटिव एजेंसियां जितनी हैं वह हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं । मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि इस तरह से पावर डेलिगेट करने से क्या फायदा होगा । इस पर मुझे ऐतराज है ।

मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि :

"which is as prescribed"

इसका क्या मतलब है ? आर्टिकल 19 मे आप ने ट्रेड पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया । हम लोग फ्री ट्रेड नहीं कर सकते हैं । आप यह भी कहते हैं कि जो फीज होगी वह भी डेलिगेटेड पावर से होगी । मान लीजिये आप कोई फीज लेना चाहते हैं

"But the rate of tax which is an essential part of declaration and assessment have been completely delegated to the executive Government with no principle or basis laid down. Uncontrolled power is vested in the Executive to fix such rate as it pleases. In the absence of legislative provision regarding any policy or limits of assessment for guidance of a legislative authority, it must be held that the provisions of the section amount to excessive delegation by legislative power, and, therefore, invalid."

आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखें, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स को देखें । सब में आपको मिलेगा टैक्स इनक्यूड्ड फीस । आपने कहा है कि लाइसेंस के लिए रुपया देना पड़ेगा एज प्रेसक्राइब्ड । इसका मतलब यह हुआ कि एक्सैसिव डैलीगेशन यहां किया गया है । उसका नतीजा क्या होगा । लाइसेंसिंग आफिस अपनी पावर्ज को एक्सरसाइज करेगा । फिर आपने रजिस्ट्रार को भी इनवाल्व किया है । इस्पैक्टर आपने अलग रखे हैं । हाई कोर्ट के जजिज का आर्बिट्रेशन अलग ले लिया है । समझ मे नहीं आ रहा है इस सब का आपका आबजैक्ट क्या है ? मान लीजिये कि एक कलाकार है या कला का प्रेमी है और वह मूर्तियां बनाता है गांव मे या किसी दूसरी जगह पर और उसके पास सौ बरस पहले की मूर्ति है जिसको देखकर वह उसको बनाता है । अब यह जो चीज है यह तो उस पर बंधन ही लगाएगी । आखिर आपका उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य यही है न कि जो सस्कृति और आर्ट के आबजैक्ट हैं और जो चोरी छिपे विदेश चले जाते हैं उनकी रोकथाम हो । उनको आप रोक नही पाए हैं जाने से, आपका कस्टम डिपार्टमैंट रोक नही पाया है, आपका पुलिस डिपार्टमैंट रोक नही पाया है, वह सजग नही रहा है और उसका नतीजा यह हुआ है कि आपने यह कह दिया है कि कला को भी हम बाधना चाहते है । अगर आपने कला को बाधा तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा । कृपा करके एकैससिव डैलीगेशन आप न करें । इससे बहुत ज्यादा नुक्सान होगा ।

लाइसेंस को रिवोक करने का प्रश्न भी आता है ।

Suppose you revoke the licence for a particular person who holds licence ; you say, I revoke today, without giving any reason. Now, you ask him : You please dispose of your property within such and such limit, within such and such months. He says : Nobody is ready to purchase it. You say, No. You say, no such thing shall be sold after a period of say, 6 months. You say, from the date of revocation of licence, Why do you say like this ? Why don't you say, you can sell proper-

ty any time but to that person who holds the licence.

आपका परपज क्या है ? आप आर्टिकल 19 आफ दी कांस्टीट्यूशन चाहते हैं या नही चाहते है । मैं रूलिंग्ज कोट कर सकता हूँ ।

In our opinion the provisions of Cl. 4(3) of the UP Coal Control Order must be held to be void as imposing unreasonable restriction upon the freedom of the trade and business guaranteed under Art 19(1)(g) of the Constitution and not coming within the protection afforded by Clause (6) of the Article I want to quote other rulings why it should be sent to the Select Committee.

कोई न आपका और न हमारा कसूर है । लेकिन

Hurriedly we pass a law People will say, Parliament has passed this law, very fine. But, what will happen is this

मेरे पास एक चीज है या एक फकीर है जो मस्जिद मे बैठता है और उसके पास एक कायन है पचहत्तर साल पुराना । वह आदमी दुनिया से अलग रहता है । अब कल को उसके पास जाकर आप कह सकते है कि तुमने रजिस्ट्रेशन नही किया है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट के पास तुम नही गए हो, इसलिए तुम को सजा दी जाती है । वह कह सकता है कि मैं अपनी जिन्दगी छोड़ सकता हू लेकिन इस आब्जैक्ट को जिस पर मेरी जिन्दगी कायम है, नही छोड सकता । ऐसा हुआ है। कला हृदय की वस्तु है । यह आर्थिक चीज नहीं और न ही यह राजनीति की वस्तु है। अगर राजनीतिज्ञों ने कुल्हाड़े से इसको तोडना चाहा और पूंजीवादी लोगों ने इसको हथौडे से मारना चाहा तो कला नष्ट हो जाएगी, कला खत्म हो जाएगी । आज भी गोआ के अन्दर हम अखबारो में पढ़ते हैं हजारों कलात्मक आब्जैक्ट्स जमीन पर पड़े हुए हैं, मन्दिरों आदि की वस्तुयें आपको वहां जंगलों में मिलती हैं, लोग इनको लेकर आ जाते हैं लेकिन आप उसको रोक नहीं सके हैं । इस बिल की जो भावना है वह तो ठीक है लेकिन जो डैलीगेशन है इसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब आप किसी भी क्लाज को पढ़ें आप एक ही वाक्य पाएंगे, एज प्रेसक्राइब्ड । कोई क्लाज आप उठायें, आप उसमें पाएं एज प्रेसक्राइब्ड ।

Licence will be granted as prescribed ; fees will be granted as prescribed. And, who has prescribed ? यह कोई आपका लैजिस्लेशन है ?

आपने आगे कहा है :

"On receipt of an application for the grant of a licence under section 7, the licensing officer may, after holding such inquiry as he deems fit, grant a licence to the applicant having regard to the following factors, namely..."

First you say, 'as he deems fit' ; then you lay down the criteria. In the end in (d) you say 'such other factors as may be prescribed'. Once you have given the criteria ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : That point is quite clear.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR Let him continue. It is very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The main difficulty is that what can be said in two sentences is blown up into a hundred or two hundred sentences.

श्री मूल चन्द डागा : I will just quote one sentence ·

"Today when the.. peril to the individual comes not from the Monarch but from the departments of State, who seek sometimes to take for themselves powers which the law has not conferred upon them, let it be remembered that it is the duty of judges to see that the individual is protected from whatever quarter he may be threatened and to see that justice is administered to him in accordance with law"—

मैं समझता हूं कि डैलीगेशन आफ अथोरिटी उतना ही होना चाहिये जितना आप कंट्रोल कर सकें । यहां तो आलटराइट डैलीगेशन हो गया है हर सैक्शन में ।

[श्री मूलचन्द डागा]

युनैस्को भी इसके बारे में कोई नाम अपनाए, इसको भी आपको देखना चाहिये। आपकी शिव की मूर्ति को हिन्दुस्तान के अलावा कोई देश एक्सैप्ट नहीं करता। जो भी है युनैस्को की मर्जी पर है। नार्म एस्टैबलिश होनी चाहियें। आपको इसके लिए लड़ना चाहिये। आपकी मूर्तियां कोई कंट्री अपने म्यूजियम में रख लेता है, कोई नहीं और कोई बताता ही नहीं है। इसके बारे में आपने इशारा भी किया है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कला की दुनिया बहुत सुन्दर दुनिया है। इसको राजनीतिज्ञ तथा पूजीवादी लोग अपने हथौड़ों से खत्म न कर दें। मैं चाहता हूं कि एक्सपोर्ट को बिल्कुल बन्द करने के पहले आप इन सब बातों पर विचार कर लें।

जब क्लाज बाई क्लाज पर विचार होगा तब मैं अपने विचार आपके सामने रखूगा। मैं इस वक्त आपकी आज्ञा न मानू और न बैठू यह भी कला का एक अनादर ही होगा। मैं समझता हूं कि आपने इस बिल की तरफ थोड़ा देखा तो आपका हम बड़ा एहसान मानेंगे।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Antiquities and Art Treasures Bill 1972. The principal objective of this Bill is to provide legislative measures for controlling the export of objects of antiquarian or historical interest or significance. This Bill also seeks to provide for the prevention of smuggling of and fraudulent dealing in antiquities The Government will have a direct say in the export of the antiquities and art treasures. The export trade which is at present in the hands of private people will be strictly controlled thereafter. At the outset, I would suggest that no export, whether it is through the State institutions or through private sources, of antiquities and art treasures, which are the torch bearers of our ancient culture and civilisation, should be permitted. If these things of historical significance and interest are permitted to be exported, it amounts to selling our ancient art and culture. I would strongly urge upon the hon. Minister of Education to ban completely the export of antiquities and art treasures.

Sir, this Bill has been formulated on the basis of ths recommendations of a Committee headed by Shri B. Venkataraman, who was a Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs. I am not able to appreciate the relationship between the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs and the antiquities and art treasures, which are thousands of years old. The news about this Bill appeared in the newspapers on 27 3.1970 and after two and a half years it has come up before this House. During the past three years, 2272 valuable art objects and antiquities had been stolen. In 1969 the number of thefts was 691 ; in 1970, 675 and in 1971, 906. So far we have found out only 415 pieces. On 18.6.1971 nearly 100 valuable paintings had been stolen from Khajurao in Madhya Pradesh. From the Prince of Wales Museum in Bombay, during 1970 about 426 bronze statues of South India had been stolen.

Last year in a place called Sivapuri in Tamil Nadu a statue was found out by a local man. He understood the value of this statue and immediately with the help of a local sculptor got an imitation of the statue made, which he surrendered to the Department. He sold away the original to a Bombaywala for Rs. 20,000, who in turn sold it to an Englishman for Rs. 2 lakhs. The Englishman then sold it to an American for Rs. 75 lakhs This is the Nataraja statue of Chola regime, which is known for its artistic beauty. A case has been instituted by the Tamil Nadu Government to recover this statue of great artistic value and cultural importance for the people of Tamil Nadu. I would request the hon. Minister, through you, to extend all his assistance to the Tamil Nadu Government in recovering this statue. If this measure had been introduced and got passed earlier, as it was announced 2½ years ago, all these thefts and large-scale smuggling could have been averted.

Sir, in 1966 a review Committee was appointed to enquire into these things. I would like to know from the hon. Minister how far the recommendations of this Review Committee had been implemented by the Government. In 1965, the Committee headed

*The original speech was delivered in Tamil.

by Sir Mortimer Wheeler, the world renowned archaeologist, submitted its report containing 25 important recommendations. I would like to know from the hon. Minister the action taken by the Government on these 25 major recommendations. Sir, I would also request the hon. Minister the reasons for the sudden resignation of Shri B. B. Lal, who was the Director-General of Archaeology. He was acclaimed all over the world as an eminent archaeologist.

Sir, the Tamil Nadu Government has given a poineering lead to other States in our country by proposing to set up an Institute for the Study of Epigraphy. The Central Government should come forward to extend all assistance in making this laudable venture a success.

In June 1970 under the auspices of UNESCO a conference of more than 80 countries, whose leading archaeologists participated in this Conference, to devise suitable measures for preventing smuggling in art objects. I do not know whether our country participated in the conference. If we had participated in this Conference, I would like to know from the hon. Minister the action taken by the Government on the recommendations made by this Conference.

Dr. V. K. R. V. Rao, the former Minister of Education, in reply to a question stated on the floor of this House that from nearly 15000 monuments of historical importance in our country every year about 1000 art objects are stolen and smuggled out of the country. Just like the gang indulging in preparing and circulating counterfeit coins and notes in the country, there is a well-organised gang which is engaged in stealing valuable art objects and smuggling them outside country. This gang is very active throughout the country, from Himalayas to Cape Camorin. I hope that through the provisions of this Bill, the Government will take effective punitive measures to smash this gang once for all. As I stated initially, I hope that the Government will ban the export of art [treasures and antiquities, whether it is through State agencies or through private agencies. After all what do we gain by selling our ancient culture and symbols of our ancient civilisation ? The party foreign exchange which we may get through this export is not tantamount to our ancient culture. We should not allow our symbols of cultural heritage to be paraded in the shops and drawing rooms of western countries. If the foreign museums want to possess something of ancient India's culture, then we can take photographs of these antiquities and supply to them. The export should be completely banned.

Sir, hundreds of old temples, the pride of Tamil Nadu, are under the control and management of the Department of Archaeology of the Central Government, I can call this as a dog in the manger policy ; the dog will not allow the cow to eat the hay nor will it eat itself. Neither the Department of Archaeology of the Central Government is able to protect and to preserve these hundreds of temples, which were built hundreds of years ago by the great sculptors of Tamil Nadu, nor the State Government is allowed to maintain and preserve them. If the Central Government had been able to give adequate protection to these temples, such a large scale thieving and smuggling would not have occurred. When the State Government of Tamil Nadu, in diference to the demands of the people of Tamil Nadu, wanted to erect a statue of Raja Raja Chola within the precints of Brhdeeswara Temple—Raja Raja Chola was the builder of this world famous temple—the Central Government refused the permission to do so. But thousands of antiquities and art objects, which are invaluable for understanding ancient India's cultural achievements are allowed to be stolen and smuggled out of India. It will be in the fitness of things that the Central Government should empower the State Governments to protect and preserve the ancient monuments and art treasures. The State Governments alone, which are nearer to the location of these monuments, will be able to preserve and maintain them.

Before I conclude, I would urge upon the hon, Minister to ban completely the export of antiquities and art treasures, I would request him also, taking assistance from the provisions of this Bill, to smash the gang engaged—I am sure that this gang consists of a number of members from affluent sections of our society—in stealing and smuggling them outside the country. The ancient culture which is the breath of the people of our country should be at all costs protected. The Government cannot barter the spring board of our cultural life for a pittance of foreign exchange. On the other hand, every effort

[Shri E. R. Krishnan]

must be made to protect, to preserve and to maintain them for posterity.

With these words, I conclude.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I would like to congratulate the Minister in charge of education for bringing such a comprehensive Bill for the preservation of antiquities and art treasures in the country. Antiquities and art treasures are not only the ruins and remnants of the past for our reminiscence, but they are a source of inspiration for the present and a guiding force in the future. From that point of view, every citizen is concerned with the antiquities of the country and art traasures that belong to us.

For the first time, in the year 1894, there was an enactment for the preservation of antiquities and art treasures in the country, but that Act was quite insufficient. In 1904, Lord Curzon, who, though he was known in Bengal as *durjan*, was a great lover of antiquities, passed an Act for the preservation of ancient monuments in the country.

In this Bill the object is stated to be twofold—to regulate the export of antiquites and art treasures and to preserve it. I would have been more happy if the emphasis had been more on the preservation side than on regulating the export of antiquities and art treasures.

Elaborate arrangements have been made for export of antiquities and art treasures from this country abroad. Certain dealers are dealing in antiquities and sometimes they are smuggling them. Thefts have occurred not only in temples and ancient places but in museums too. There are newspaper reports that certain valuable antiquities have been removed from certain museums. It is anybody's guess that employees of the museums are also involved in such thefts. Therefore, along with the measures taken for regulating this trade, government should ensure that no employee is in any way involved in such smuggling or trade. Drastic action should be taken against those persons who are suspected of doing such things or who have been in collusion with smugglers and thieves.

Since I may not get a chance to speak on the clauses, I would like to make my observations on some of the clauses. Clause 3 says that the Act may come into force in different States on different dates. An unscrupulous person may remove an antiquity from a State where the Act is in force to another State where it is not in force and thereby may go scotfree Therefore, I would suggest that the Act should come into force in all the States on the same date so that such things cannot happen.

Clause 2(25) says that antiquities should be at least 100 years old and in a subsequent clause it is stated that at least 75 years time should pass. I would suggest a period of 50 years, instead of 75 years, on the pattern of the Copyright Act which provides that after 50 years of the death of an author a manuscript becomes a national property.

Then there is a provision for an expert committee. It is not mentioned anywhere clearly except in the expenditure item where it is mentioned that for TA and DA some amount may be necessary I do not know what will be the composition of such an expert committee. The Director-General of the Archaeological Survey of India is made the sole arbiter in some matters. Archaeology has three main branches, namely, iconography, epigraphy and numismatics. He has nothing to do withpainting and other things. Therefore, if he is not having the advice of experts, he will not be in a position to decide which matter is really of great value and which is not. Therefore, there must be provision of a statutory nature to have an experts committee to advise the Director-General of Archaeology.

In clause 8, which deals with the qualifications of dealers, exemption has been provided in the case of those dealers where ten years have expired after their conviction for smuggling or theft. Why should such leniency shown or concession given to a person who has been convicted of smuggling or theft of art treasures? Once a person is convicted, he should never be appointed again.

MR DEPUTY-SPEAKER: May I point out that at this stage the clauses cannot be referred to individually? He can only refer to the principles.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : I may not get a chance to speak on the clauses.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That does not mean that the procedure should be violated.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Therefore, I do not refer to particular clauses.

I would like to say regarding general provision that there must be great emphasis on the preservation of those antiquities and art treasures in the country.

The museums run by the civic bodies and registered societies should also be given some sanctity and protection so that they can also collect, preserve and exhibit such things for the benefit of the public. Here, I have seen only the Government museums and other things that are provided.

In order to regulate exports, I would like to say that there should be some prohibitory order to the effect that certain things, certain antiquities, certain art treasures, should not be exported under any circumstances because these are precious things. They cannot be sold out.

I would like to conclude by saying one thing Regarding the fixation of price where the compulsory acquisition is provided, in the first place, it has been provided that it will be by an agreement between the seller and the officer who acquires it. It is our common experience that even inferior things are sold at higher prices. Therefore, there must be some adviser or an expert committee to determine the price of such antiquities. Otherwise, a thing of inferior value may be sold at a higher price and the thing of superior value may be sold at a lower price.

With these words, I commend the Bill for the acceptance of the House.

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसको देख कर तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि इसके आने में देरी हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों में यह बात अब साफ सामने आई है कि भारत से चोरी छिपे अवैध रूप से कलाकृतियां बाहर जाती हैं और उसको रोकने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं । लगभग कई शताब्दियों से देश आक्रमणकारियों के पंजे में फंसता रहा और इसकी वजह से देश की काफी कलाकृतियां नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी हैं । एक समय ऐसा था जब कि मूर्ति तोड़ने में बड़ा बहुमान समझा जाता था । किन्तु जमाना बदल गया है । आज हर चीज पैसे से नापी जाती है । आज जब पता चला कि मूर्ति तोड़ने के बजाय उसको बाजार में बेचा जाय तो उससे ज्यादा मूल्य प्राप्त होता है, मुनाफा ज्यादा आता है, तो अब यह काम शुरू हो गया । यह एक नया विचार आज इस जमाने का है । इसकी ओर भी मैं शिक्षा मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह भी शिक्षा मंत्रालय का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है । जिस संस्कार की वजह से यह होता है उसकी किसी ने संज्ञा दी है देशद्रोह की । मेरे कुछ कम्युनिस्ट मित्रों ने कहा है कि अच्छी-अच्छी कलाकृतियो और पुरावशेष को बाहर विदेशों में चोरी-छिपे अवैध रूप से बिक्री करना यह देश के साथ धोखा है ।...(व्यवधान) इसके तीन पहलू है । एक तो यह है कि कई ऐसे असुरक्षित स्थान है जहां ये पड़ी है, जैसे एक का नाम मैं बता देना चाहता हू—महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले मे खिद्रापुर । पुरातत्व विभाग यही समझता है कि वहां एक सूचना फलक लगा देना काफी है और इसके बाद फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई । यहां तक कि वहां जाना है तो पता नहीं लगता कि यह स्थान कहां है । इतना बढ़िया मन्दिर, किन्तु कोई सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण वे कलाकृतियां नष्ट हो रही हैं और आसानी से चोरी हो जाती हैं । आज भी अपने देश में ऐसी अनेकों कलाकृतियां हैं, जो टूटी-फूटी नहीं, अच्छी स्थिति मे पड़ी हुई हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वे मूर्तियां कहां पड़ी हुई हैं । आज के अखबार में एक समाचार है—

"Seven idols have been found near Thanjavur. Seven idols including those of Lord Vishnu and his consort were found at

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

Avanianallur near here last week. The idols made of five metals were said to be archaeologically important,"...

Now they have been handed over to the police.

किन्तु ऐसी मूर्तिया कहां-कहां पड़ी हैं, यह अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसका कारण केवल यही है कि इस देश में एक हवा चली कि जो-जो पुराना है, वह मानों त्याज्य है, घृणास्पद है, इसी की वजह से यह हवा फैली कि आज अच्छे मन्दिरों में भी लोग नहीं जाते, तो पुराने मन्दिरों में कौन जायगा, पहाड़ पर बने मन्दिरों में कौन जायगा, जंगलों में बने मन्दिरों में कौन जायगा, वहां पर क्या चीज है, किस को पता चलेगा। इतना ही नहीं विजयनगर के पुरावशेष को देखिये, वहां पर सूचना लगा दी गई है कि जो खराब करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन गणपति की शुण्ड टूटने के बाद उसमें खराब करने को क्या शेष रह जायगा। बाद में आप बोर्ड लगा दीजिये कि जो खराब करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी, तो इससे क्या होगा। किन्तु जिस विचारधारा की वजह से वह कलाकृति नष्ट हुई, उसके लिये कौन दोषी है।

14 hrs.

मुझे एक किताब में पढ़ने का अवसर मिला—वह किताब का लिखने वाला एक अंग्रेज है—जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में ऐसी कला-कृतियों को नष्ट-भ्रष्ट करना शुरू किया, तो जो उनकी रक्षा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप हमको मारिये, लेकिन इन कलाकृतियों को मत तोड़िये। फिर भी उन्होंने नहीं माना, बेओनट चलाया और मूर्तियों को तोड़ा। अंग्रेज जो कहता था कि हम सिविलाइज्ड हैं, हिन्दुस्तान की सारी जिम्मेदारी लेंगे, इट इज ए व्हाइटमैन्स बर्डन—उस अंग्रेज ने भी हिन्दुस्तान की कलाकृतियों को कम नष्ट नहीं किया।

इतना ही नहीं, उनके राज्य की वजह से अपनी कई रियासतों से अच्छी से अच्छी वस्तुयें, बहुमूल्य चीजें, उनका आदरभाव दर्शाने के लिए, वहां भेजी गईं। चोरी-छिपे ले गये, जबरदस्ती ले गये—जैसे कोहिनूर गया, जैसे शिवाजी महाराज की खड्ग, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, ले गये। मैंने दो बार यहां पर सवाल उठाया, हमारा देश इस पर गौर करे—जिन वस्तुओं से हम प्रेरणा लें, ऐसी चीजें हिन्दुस्तान से बाहर क्यों रहें। चूंकि अंग्रेज विजेता था, इसलिए वे चीजें वहां गईं, लेकिन अब तो वे वापिस आनी चाहियें। हमारी इण्डिया हाउस लाइब्रेरी है, उसको वापस लाने के लिए श्री हुमायु कबीर जी ने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु आगे चल कर शिक्षा मंत्रालय ने उस चीज को क्यों छोड़ दिया—यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उसको अब वापिस क्यों नही लाते। विजेता के रूप में जब चीज चली जाती है तो जब सामान्य स्थिति पैदा हो जाती है तो उसको वापिस क्यों नहीं लाते? हिटलर के आक्रमण के दिनो मे बहुत सी कलाकृतियां और अन्य चीजें यूरोप के देशो से वहां लाई गईं, लेकिन स्थिति बदलने के बाद उन चीजों को उन देशो को लौटाया गया। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है कि हिन्दुस्तान सरकार साहस लेकर इन चीजों को वापस लाने का प्रयत्न करे। जहां-जहां म्यूजियम्ज है और उनमें जहां-जहां भारत की चीजें दिखाई देती है, जब तक उनकी वैध बिक्री का पता नहीं चले, तब तक उन को चोरी किया हुआ सामान ही समझा जायेगा। इसलिए साहस लेकर हमारी सरकार कहे कि जहां-जहां हमारी चीजें गई हैं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Can that be provided in this Bill?

श्री जगन्नाथराव जोशी : This can be the second Bill, I am giving certain suggestions that it should be modified. When Government would like to stop exports and smuggling, Government can go a step forward.

अपनी चीज जब हम को मालूम हैं और साबित होने के बाद भी हमको वापस नहीं मिलती तो हमारी आजादी के गौरव का मतलब क्या होगा।

हमारे पूना में एक राजा केलकर संग्रहालय है, उन्होंने बहुत सी पुरानी चीजों का संग्रह किया है। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है, किन्तु

उससे भी पिछले दिनों बहुत सी चीजें चोरी गई हैं। जो एक व्यक्ति कला के पीछे पड़कर स्वयं ऐसी चीजों का संग्रह करता है, मैंने स्वयं जाकर उनके संग्रहालयों को देखा है, वृद्ध होते हुए भी जब इतनी सारी चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया है, तो मैं हैरान रह गया जब एक रेलवे पास जैसी मामूली चीज भी कैंसिल कर दी गई। खुद तो करते नहीं और यदि कोई कला के पीछे पड़ कर स्वय ऐसी वस्तुओं को देखकर आये, उनको संग्रहीत करने का प्रयास करे, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि उनको रजिस्ट्रेशन और लायसेंस के लिए कोई कानूनी तकलीफ न हो।

एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा—जैसे यहां की कला-कृति को तोड़ा गया, किन्तु आज जैसे कलाकृति की बिक्री हो रही है, वैसे यहां विचार की बिक्री भी हो रही है। मानों देश राम-कृष्ण को भूल गया, किन्तु आज राम-कृष्ण का नाम अमरीका और इंग्लैंड मे सुनाई देने लगा है। वहां भी राम-कृष्ण की मूर्तियां पैदा होने लगी है। इसमें कोई चोरी-छिपे जाने का सवाल नहीं है, यहां जैसी मूर्तियां है, वैसी ही मूर्तियां अमरीका में बन रही हैं, इंगलैंड में बन रही हैं तो आगे चल कर हमारे यहां पत्थर की सुन्दर मूर्ति मे जो सजीवता देने की क्षमता थी—यह विचार बड़े महत्व का है, यह विचार यदि दुनिया से जाता है, अपनी मूर्तियां वहां भी खड़ी होती है, अपनी कलाकृतियां वहां भी खड़ी होती हैं, भारत का इतिहास वहां भी जाता है तो हमें इसमें खुशी है—लेकिन जब तक हमारे देश से जो चोरी छिपे जाता है, उस चोरी पर साहसिक कदम नहीं उठायेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा और यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है तो हम जरूर उसका स्वागत करेंगे।

SHRI BANAMALI PATNAIK (Puri) : Sir, this is a welcome measure though long overdue.

In this connection, I would like to mention a few points. There are a large number of temples in Orissa which are in dilapidated condition but not protected under the Ancient Monuments Preservation Act. There are only, as Mr Jagannatha Rao Joshi just now said, sign-boards, and there the duty ends.

I would like to mention here about the village of Hirapur where there is the temple of Chausati Joginis. Unfortunately, some of the Joginis have been stolen away though the temple is preserved by the Government of India. Similarly, in the village of Chaurasi, there are 84 temples and 84 deities but there is only one temple preserved, known as Barahi temple. That is the only temple protected but it is only preservation by name. The temple has developed cracks and it is susceptible to rain and destruction. No steps have been taken for its repairs. There is only one guard posted there to look after these monuments but he does not stay there.

Then there are a large number of small deities in that Prachi valley which were excavated by the Government of India at a cost of a few lakhs but the excavations are not preserved. Many of them have been stolen away and we do not know where they have gone. They have gone with the connivance of those in charge of them Otherwise, these things could not have happened.

Recently there has been an excavation done in Ratnagiri by Smt. Devala Mitra who excavated but all those things are not to be found there. They have been removed from that place because that place is not accessible. If that place is not accessible and if you go there, how can you read the history ? If there are such places, those places should be preserved and a museum should be attached there.

There is another temple which is known Alala Nath, derived from the word 'Alwars' and this temple which is connected with the Jagannath temple of Puri has its importance because of the Twelve Alwars and it has some connection with Tamil. All the inscriptions there and the *Tamra Patras* have been lost. I myself reported it to the Government of India. Dr Raghavan of Madras University is aware of it as I had personally told about the *Tamra Patras*. But these things are now missing because there was no proper authority to be handed over for preservation.

Now, another point. If you do not know what are the monuments to be preserved, how

[Shri Banamali Patnaik]

can you control the exports ? There must be a list maintained by the officer of the Archaeological Department who must be empowered to take photo copies of it and a copy must be available with all the District Officers. Now, Orissa is attached to the Calcutta Circle. The Eastern Circle is very big. Therefore, a separate circle at Bubaneswar will help in proper preservation of these ancient monuments in which Orissa abounds. There is only a junior officer in Bubaneswar. He did not know anything. He is not a competent officer to deal with such things. There must be some higher authority to maintain all these monuments and records. Also as I said earlier, photo copies of these things should be taken and a list maintained so that whenever he is transfered, the incoming officer is aware of the details of preservation.

There is one temple, the Raj Rani temple in Bubaneswar. All the land around it has been leased out and the temple has lost all its beauty because of the slums springing up near about. Some of the *Parsva devtas* have been stolen away. This happens even in the capital city. These things are happening because there is no preservation or protection. Then the connivance of the officials also is there. It is said that to prepare a *murti* is less costly than to sell it because it fetches a high price. There are various other things which are not yet controlled under this Act. Let us have a rule how all these things should be controlled and should be preserved.

An object of art is a priceless beauty. An art object may be of value of Rs. 15,000 and it may be of the value of Rs. 1 lakh to somebody else. So you cannot have an arbitration about the price of an art object There is the Malwala palace of Raja Dharamkaran where I attended a dinner ; Mr. Chandulal Trivedi was there. Large number of beautiful paintings were there. These are from the Moghul period. It is said that these paintings were from the days of Akbar. It is preserved there. He wanted to hand it over to the Department in the meanwhile something has been lost. I do not know what has happened to it.

The Jagannath temple at Puri has not been declared as an ancient monument of national importance under the Preservation of Ancient Monuments Act. It is now under the State Government's management. Certain cracks have appeared. The Governor of Orissa, Mr. Joginder Singh appealed to the public for its repairs. Is it possible for the public to do it ? The temple is known for its magnificence and grandeur. So many foreigners come and visit the temple. Once such cracks begin to appear what will happen ? How can the temple be preserved ? There are *Pandas* and *Sevayats*. They are responsible for preservation of the deities only they are in charge of. But what happens is, some other people take away the smaller deities from inside the temple. You will see some of the places just remaining vacant. There should be a list of these deities for preservation.

There is the Madalapanji in the temple at Jagannath which has been preserved for 800 years. Photostat copies should be printed and distributed to all the other museums. Herein is written how Shankaracharya and Guru Nanak visited the temple and worshipped it. If such photostat copies are sent to other museums it will be of great use to those museums and it will ensure that there will be no chance of destroying this Madalapanji (chronological history).

The British people did not care for the preservation of art objects. During the British period many were lost. One Mr. Biren Roy of Puri collected some beautiful pieces of architecture and sold them to British people. He got OBE. MBE and other titles.

In the Institute of Sanskrit at Puri there were large number of Sanskrit manuscripts which were rare. Dr. Raghavan, Prof. of Sanskrit of Madras University visited and examined them and he recommended for their publication. But some of them are missing. Some of these Sanskrit books which are rare things are in Deutsche museum at Munich and in the Albert Hall in London, How could these things go away ? We should prevent that. It is very important that we should preserve them. I agree with what Mr. Daga has said. The Bill is defective in the sense that it will not help in preservation of these articles. I request the Minister to see that a more comprehensive Bill is brought forward. Thank you.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : I am extremely grateful to the hon. Members who

have taken part in this Debate. It is an extremely encouraging sign. It shows the concern of the whole nation in the matter of preservation of art treasures and its cultural antiquities. I know that the time allotted for the discussion is already over. I shall attempt to be as brief as possible and I will resist the temptation of going into all the points that have been raised.

I can only make one general submission, namely that Government are deeply benefited by the suggestions which have been offered by hon. Members, and we shall try to do our best to see that as many of these suggestions as can be acted upon are in fact acted upon.

There are just a few points to which I would make a very brief reference. Firstly, in regard to the birth-place of Raja Ram Mohun Roy, the house which is there in the village Radhanagar was inspected, and the inspection revealed that the only structure that stands at the site today is a modern structure called the Ram Mohun Smriti Mandir. The ancestral house of the Raja at Raghunathpur is reduced to a few broken walls while the house .....

SHRI MANORAJAN HAZRA (Arambagh) : Perhaps the hon. Minister has misunderstood what I had said. I was referring to the ancestral house which is in Calcutta, and which is there on the Upper Circular Road under the Police Commissioner

PROF. S. NURUL HASAN : I was just coming to that. So far as the Calcutta house is concerned, one of my friends here, an hon. Member from Calcutta has raised this question with me, and I have started corresponding with the Government of West Bengal, and I hope that after a proper inspection is done, some way out will be found.

So far as the Hazarwali Palace at Murshidabad is concerned, the Government of India have decided to bring this under protection as a monument of national importance, and we are in touch with the Government of West Bengal.

I have been alarmed to hear, and I had heard it in the other House also, and I heard this point raised by an hon. Member here about the thefts there. We have started taking action. I did not know about it until it was raised in Parliament, and we will do our best to see that objects are not smuggled out.

With regard to the gracious lady, the hon. Member from Jaipur, I would not have liked to comment upon some of her observations in view of the tremendous personal esteem in which I hold her, but in order to set the record right, I have to make at least a couple of observations.

It is not a fact that the thefts of our art objects have increased since Independence. I have had the occasion to work in the various museums in England and in Europe, and all those beautiful collections from India which are to be found there were taken out before Independence and not after Independedce.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : I thank the hon Minister very much for pointing this out to me, because obviously he knows more about the subject. Since 1941, ever since they made this Act, and even before that, as the hon. Member there pointed out, there were many things which went to the British Museum, because after all, India was part of Britain, and so it is quite natural that a quite fabulous collection went to the Dublin Museum and other museums in England. We all knew about it... ...

PROF. S. NURUL HASAN : As far as I recall, she made the statement that thefts and smuggling had started after Independence. For example, if an Indian Prince gave an Indian art object to a Viceroy as a present, would it not be theft and smuggling ? . .....

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : It is the same as if the President gave a gift and so on to the President of the USSR or somebody like that. It is just the same thing.

PROF. S. NURUL HASAN : I must confess that the scales of value judgements are a little different.

I am conscious of the fact that there are many princely rulers who took great care to preserve works of art and to preserve their records. Unfortunately, some of them did not pay enough attention to even this aspect.

[Prof. S. Nurul Hasan]

For example, if I may make a personal confession, in spite of the kindness of the gracious lady to help me see the records of Akbar's reign in the house of Jaipur there are no records so far located of Akbar's reign. This is so surprising, considering that there was no noble who was closure to Akbar than Raja Man Singh, and even though in petty houses in various parts of U.P., Punjab and Rajasthan, documents of Akbar's reign are available, it is very surprising that in the house which was closest to Akbar there is no document of Akbari period available.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : I am afraid, and I know, that in the house of Jaipur, there is no document of Maharaja Jai Singh either. The Rajasthan Government have taken them all.

PROF. S. NURUL HASAN : I am referring to the documents I had occasion to see earlier ; as I said, nothing pains me more. But I must submit that I am a professional historian. I have been going into these matters. I have been taking interest in these matters. All that must say is that I wish this consciousness of records and of the art treasures had been as universal as is the desire of this whole House, and I share that desire, and I think that all our people are becoming more and more conscious of their importance.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : May I just ask the hon. Minister one thing ?.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is one too many.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : It is nothing to do with Rajasthan or Jaipur. I am referring now to the Palace in Calcutta ; it is falling into pieces. I am asking the hon. Minister to recommend that to the West Bengal Government for being taken over.

PROF. S. NURUL HASAN : I wish this had been an occasion to discuss the functioning of the Archaeological Survey of India. I would be very glad to answer all the questions that have been raised by the hon. Member, but unfortunately, the scope of the Bill is rather limited. Therefore, I purpose to confine my remarks to some of the points that have been raised. A point has been quite rightly raised that there might be procedural difficulties in registration. I can give this assurance to the House that when framing the rules, we shall take proper care to ensure that the registration is facilitated.

My hon. friend Shri Jharkhande Rae has made one observation which has pained me, and I consider it my duty to make a statement about that. That is with regard to the Director-General of Archaeological Survey of India and to the officers of the Archaeological Survey of India. If there is any specific complaint, I any willing to look into it, but I feel that it is most unfair to have such a general charge being mentioned in the House. I would like to state that I have my confidence in the officers of the Archaeological Survey of India, and I wish to take this opportunity of paying a tribute to their ability and to the devotion with which they have been doing their work

As regards the point raised by my hon. friend Shri M. C. Daga, I am afraid I am unable to understand part of the point.....

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Kangra) : He may be asked to repeat it again.

PROF. S. NURUL HASAN : I just do not know how this is going to stifle art. I think that there is no question of any living artist being brought within the purview of the present Act.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : Whom will the artists produce for ?

PROF. S. NURUL HASAN : If she wishes to have a dialogue, I am quite willing, and I request I may be permitted to use rather strong words.....

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : What Shri M. C. Daga meant was 'whom will the artist produce for ?'

PROF. S. NURUL HASAN : I am in your hands, Sir. If you permit me, I shall answer every point raised by the hon. lady.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Please permit him, Sir, because we want to hear him.

PROF. S. NURUL HASAN : Sir, the important point that has been raised by the hon. Member is with regard to the fees, and he referred to all the rulings about taxes. A fee is not a tax, and there is a basic difference between a fee and a tax, and, therefore, that point does not arise.

I had referred in my original speech to the fact that at the UNESCO convention, certain countries were dragging their feet. Unfortunately, this House does not have control over the UNESCO, It has only control over the the Indian delegation which goes and makes a submission to the UNESCO. Therefore, to leave the question of the export of antiquities to UNESCO over which this House has no control, does not, I think, meets with the wishes of this House.

My hon. friend from the DMK probably did not bother to listen to my short and brief introductory speech. Otherwise, he would not have raised some of the points which he raised. I admire him for taking every opportunity to say how wonderful the government of Tamil Nadu is.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is his job.

PROF. S. NURUL HASAN : That is his job. I remember a statement by Ichhkov of Russia. In 1875, he started a war scare by saying "If Germany attacks France, then Russia would go to the assistance of France." Then Bismarck remarked that "If Ichhkov so desires, I am quite willing to have five-franc pieces struck with the legend 'Ichhkov, the protector of France'. But why start a war scare ?"

I entirely agree that the antiquities should not be exported for money. That point has quite rightly been made out. Even the Central Government cannot now export without undergoing all the processes—

SHRI S. M. BANERJEE : The point raised by Mr. Jharkhande Rai was that they are being sold by those Rajas.

PROF. S. NURUL HASAN : After this Bill, it will not be possible. That is why I have pleaded in this House that this Bill may be approved as soon as possible, and if any further points are to be raised, I am quite willing to come before this hon. House and say, "Please add this one and please add that one."

SHRI S. M. BANERJEE : Unless it is assented to by the President, they can sell them.

PROF. S. NURUL HASAN : No. The present rules have certain lacunae, although even with the present rules, export without licence is not possible. This Bill is seeking to plug all these loopholes so that it should not be possible to sell any of our antiquities abroad. That is the whole intention of the Government.

The question of the Brihadeeswara temple was raised by my hon. friend. I had a talk with my colleague, the Education Minister of Tamil Nadu, and there, I said, let us appoint a committee consisting of the Director of Archaeology of Tamil Nadu, a representative of the Director-General of Archaeological Survey of India and any professor of archaeology or ancient history in any of the universities of Tamil Nadu. Let them say that from an expert point of view the site which was chosen for installing a modern statue was proper. Then I would accept it. I do not think that these matters should be made into a question of Centre-States controversy We are all on the same side of the fence. There is no difference between the States and the Centre in the desire to preserve our antiquities. But it was a question of the specialists. versus the generalists. I have every respect for the generalists, but there are occasions when expert opinion ought to be accepted.

I had the privilege of being a member of the Wheeler Committee myself, and I can assure the hon. Member that I shall do all that lies in my power to see that its recommendations, as far as they lie within the power of the Government, are implemented as quickly as possible.

The hon. Member Shri Shastri raised the question of authority. That has to be determined by the rules. So far as the question of price is concerned, there is already an Art Purchases Committee, a Committee of experts, which takes decisions on these points.

I entirely agree that every step should be taken to see that the protected monuments are

[Prof. S. Nurul Hasan]

really protected. The Government of India have recently appointed a very large number of chowkidars to look after the monuments to ensure that thefts do not take place. We are also considering several steps and getting the co-operation of the State Governments for this. This point, which was raised by Shri Jagannathrao Joshi, is quite correct. I entirely agree with him. My only point is that I do not know whether I can prohibit the export of thought from India.

SHRI MANORANJAN HAZRA : I raised the question of Kohinoor, which is a matter of national honour. I want some clarification on this.

PROF. S NURUL HASAN : If it had been in the power of this House, I would have run to Britain and brought it back myself.

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : I am not trying to have a dialogue. Has the Kohinoor originally come from India or from Persia ?

PROF. S. NURUL HASAN : Originally it has come from what is now known as Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put to the vote amendment No. 1 moved by Shri M. C. Daga for reference of the Bill to a Select Committee.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to regulate the export trade in antiquites and art treasures, to provide for the prevention of smuggling of, and fraudulent dealings in, antiquities, to provide for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures for preservation in public places and to provide for certain other matters connected therewith or incidental or ancillary thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2—(*Definitions*)

Amendment made :

"Page 2,—

for lines 9 and 10, *substitute*—

"for the purposes of this Act, which has been in existence for not less than one hundred years ; and" (2)

(*Prof. S. Nurul Hasan*)

SHRIMATI GAYATRI DEVI OF JAIPUR : I beg to move :

Page 2,—

omit lines 1 and 2. (13)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No. 13, moved by Shrimati Gayatri Devi, to the vote of the House,

Amendment No. 13 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3—(*Regulation in export trade in antiquities and art treasures*)

SHRI M. C. DAGA : I beg to move :

Page 2,—

after line 32, *insert*—

"Provided that in special circumstances, the person who wants to export any antiquity or art-treasure and has obtained the permission of the prescribed authority, may export the same." (3)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No. 3, moved by Shri Daga, to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 to 7 were added to the Bill.

Clause 8—(*Grant of licence*)

SHRI M. C. DAGA : I beg to move :

Page 3, lines 23 and 24,—

omit "after holding such inquiry as he deems fit," (5)

MR DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No 5, moved by Shri Daga, to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 8 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 11 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are two amendments given notice of by Shri Daga. Is he moving them ?

SHRI M. C. DAGA : I am not moving them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then, I put clauses 12 to 17 together to the vote of the House.

The question is :

"That clauses 12 to 17 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 12 to 17 were added to the Bill.

Clause 18—(*Provisions of sections 14, 16 and 17 not to apply in certain cases*)

SHRI M. C. DAGA : I beg to move :

Page 6, line 25,—

add at the end—

"and in the educational institutions and places of worship " (8)

PROF. S. NURUL HASAN : I beg to move :

Page 6, line, 24—

for "archive," *substitute*—

"archive ; or" (11)

Page 6,—

after line 24, *insert*—

"(iv) in an educational or cultural institution," (12)

SHRI M. C. DAGA : They have accepted one part of my amendment already. These words "educational or cultural institution" have been added by an amendment moved by the Government. I have mentioned also "Places of worship". But they say, only educational or cultural.

PROF. S. NURUL HASAN : My point is that the place of worship cannot be owned, controlled and managed by the Government. Therefore, I have re-phrased it to bring it under the qualifying clause educational or cultural institution owned, controlled and managed by the Government.

SHRI S. M. BANERJEE : There is a contradiction. He says that the place of worship cannot be controlled by the Government. It is felt by everybody that God is everywhere. When they are controlling all the other places, why should they not control temples and other places of worship also ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : First I put amendment No 8 moved by Shri Daga to the vote of the House.

Amendment No. 8 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, I put amendment Nos. 11 and 12 to clause 18

[Mr. Deputy-Speaker]

moved by Prof. Nurul Hasan to the vote of the House.

The question is :

Page 6, line 24—

for "archive," *substitute*—

"archive ; or" (11)

Page 6,—

after line 24, *insert*—

(iv) in an educational or cultural institution," (12)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 18, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clause 19—(*Power of Central Government to compulsorily acquire antiquities and art treasures*)

SHRI M. C. DAGA : I beg to move :

Page 6, lines 33 to 35,—

for "and it shall be lawful for the Collector to take possession of such antiquity or art treasure, for which purpose the Collector may use such force as may be necessary."

substitute

"and if the owner of the antiquity or art treasure objects to the decision of the Government, he may within a period of thirty days from the date of the intimation, make a representation to the Central Government putting forth his objections." (9)

Page 6,—

omit lines 36 to 40. (10)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put Amendments 9 and 10, moved by Shri M. C. Daga to Clause 19 to the vote of the House.

Amendments Nos. 9 and 10 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 19 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 19 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are no further amendments. I shall put the rest of the Clauses and the rest of the Bill to the vote of the House.

The question is :

"That Clauses 20 to 33, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 20 to 33, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. S. NURUL HASAN : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

14.42 hrs.

MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI